बुंदेलखंड में बहेगा खुशहाली का पानी

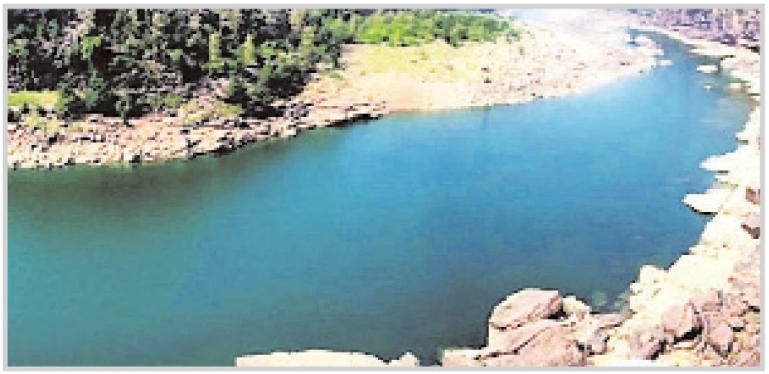

केन-बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के साथ-साथ मध्य प्रदेश के दूसरे हिस्सों को भी लाभ मिलेगा। 44 हजार 605 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना के मूर्त रूप लेने के बाद 103 मेगावॉट जल विद्युत और 27 मेगावॉट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न की जा सकेगी। एक ओर जहां इससे बुंदेलखंड में औद्योगीकरण और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, वहीं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

भारत सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी सभी बुनियादी बाधाएं पहले ही दूर हो गई थीं। इस परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए 44,605 करोड़ रुपए की राशि देने का प्रावधान किया गया था, जिसकी 2022-23 के बजट में पहली किश्त के रूप में 1400 करोड़ रुपए प्रस्तावित कर दिए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपयी ने नदी जोड़ो अभियान की जो परिकल्पना की थी, उसे नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। इस परियोजना को जमीन पर उतारने के परिप्रेक्ष्य में मध्य-प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली अंतरराज्यीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाले समझौता-पत्र पर पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे। यह मंजूरी जल शक्ति अभियान कैच द रन के तहत अमल में लाई जाएगी। साफ है, इस परियोजना से कृषि तो फले-फूलेगी ही, कृषि आधारित उद्योग भी पनपेंगे और लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा।

बाढ़ और सूखे से परेशान देश में नदियों के संगम की परियोजना मूर्त रूप लेने जा रही है, यह देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है। 5500 अरब रुपए की इस परियोजना को जोड़ने का अभियान सफल होता है तो भविष्य में 60 अन्य नदियों के मिलन का रास्ता खुल जाएगा। दरअसल बढ़ते वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन और बदलते वर्शा चक्र के चलते जरूरी हो गया है कि नदियों के बाढ़ के पानी को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहरों के जरिए भेजा जाए। ऐसा संभव हो जाता है तो पेयजल की समस्या का निदान तो होगा ही, सिंचाई के लिए भी किसानों को पर्याप्त जल मिलने लग जाएगा। वैसे भी भारत में विश्व की कुल आबादी के करीब 18 प्रतिशत लोग रहते हैं और उपयोगी जल की उपलब्धता महज चार प्रतिशत है। हालांकि पर्यावरणविद् इस परियोजना का यह कहकर विरोध कर रहे हैं कि नदियों को जोड़ने से इनकी अविरलता खत्म होगी, नदियों के विलुप्त होने का संकट बढ़ जाएगा।

कृत्रिम रूप से जीवनदायी नर्मदा और मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदियों को जोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कर चुके हैं। चूंकि ये दोनों नदियां मध्य-प्रदेश में बहती थीं, इसलिए इन्हें जोड़ा जाना संभव हो गया था। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की तैयारी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें बहुत पहले से जुटी थीं। इस परियोजना को वर्ष 2005 में मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन पानी के बंटवारे को लेकर विवाद बना हुआ था। उप्र को रबी फसल के लिए 547 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) और खरीद फसल के लिए 1153 एमसीएम पानी देना तय हुआ था। मुख्य विवाद रबी फसल के लिए पानी देने को लेकर था। अप्रैल 2018 में उप्र ने इस फसल के लिए 700 एमसीएम पानी की मांग रखी, जो बाद में 788 एमसीएम तक पहुंच गई। इस पर सहमति बनती इससे पहले उप्र ने जुलाई 2019 में पानी की मांग बढ़ाकर 930 एमसीएम कर दी। मप्र इतना पानी देने को तैयार नहीं हुआ, लिहाजा विवाद बना रहा। किंतु अब केंद्र और दोनों प्रदेशों की सरकारें भाजपा की होने के चलते 35,111 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिल गई है।

परियोजना में पांच-पांच फीसदी राशि राज्य सरकारें खर्च करेंगी और 90 प्रतिशत की बड़ी राशि केंद्र सरकार देगी। केन नदी जबलपुर के पास कैमूर की पहाड़ियों से निकलकर 427 किमी उत्तर की और बहने के बाद बांदा जिले में यमुना नदी में जाकर गिरती है। वहीं बेतवा नदी मध्य-प्रदेश के रायसेन जिले से निकलकर 576 किमी बहने के बाद उत्तर-प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में मिलती है। केन-बेतवा नदी जोड़ो योजना की राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार डोढ़न गांव के निकट 9000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बांध बनाया जाएगा। इसके डूब क्षेत्र में छतरपुर जिले के बारह गांव आएंगे। इनमें पांच गांव आंशिक रूप से और सात गांव पूर्ण रूप से डूब में आएंगे। कुल 7000 लोग प्रभावित होंगे। इन्हें विस्थापित करने में इसलिए समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये ग्राम जिन क्षेत्रों में आबाद हैं, वे पहले से ही वन-सरंक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित हैं।

इस कारण रहवासियों को भूमि-स्वामी होने के बावजूद जमीन पर खेती से लेकर खरीद-बिक्री में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण यह इलाका मुआवजा लेकर आसानी से छोड़ देंगे। ऐसा दावा प्राधिकरण की रिपोर्ट में किया गया है। इस परियोजना के बहुआयामी होने के दावे किए जा रहे हैं। बांध के नीचे दो जल-विद्युत संयंत्र लगाए जाएंगे। 220 किलोमीटर लंबी नहरों का जाल बिछाया जाएगा। ये नहरें छतरपुर, टीकमगढ़ और उत्तरप्रदेश के महोबा एवं झांसी जिले से गुजरेंगी। जिनसे 60,000 हेक्टेयर कृशि भूमि की सिंचाई होगी। विस्थापन और पुनर्वास के लिए 213.11 करोड़ की आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, जिसका इंतजाम मंजूरी के साथ केंद्र सरकार ने कर दिया है। डीपीआर के मुताबिक उत्तर-प्रदेश को केन नदी का अतिरिक्त पानी देने के बाद मध्य-प्रदेश करीब इतना ही पानी बेतवा की ऊपरी धारा से निकाल लेगा।

परियोजना के दूसरे चरण में मध्य-प्रदेश चार बांध बनाकर रायसेन और विदिषा जिलों में नहरें बिछाकर सिंचाई के इंतजाम करेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इन प्रबंधनों से केन में अकसर आने वाली बाढ़ से बर्बाद होने वाला पानी बेतवा में पहुंचकर हजारों एकड़ खेतों में फसलों को लहलहाएगा। मध्य-प्रदेश का यही वह मालवा क्षेत्र है, जहां की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण सोना उगलती है। इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो जाता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खेत साल में 2 से लेकर 3 फसलें तक देनें लग जाएंगे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 14 जिलों को मिलाकर बना बुंदेलखंड क्षेत्र दशकों से सूखे की मार झेलता आ रहा है। वर्षों से लंबित केन-बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद इस क्षेत्र की यह समस्या दूर हो सकती है। यह परियोजना खेती और पीने के पानी की कमी दूर करने के साथ इस इलाके में पलायन पर भी रोक लगाने में मददगार हो सकती है।

पानी की कमी बुंदेलखंड क्षेत्र की हमेशा से एक प्रमुख समस्या रही है। पर्याप्त मात्रा में खेती के लिए पानी न मिल पाने से फसलों की उपज प्रभावित होती है, तो आम जनता को भी दैनिक जीवन में पानी की किल्लत से दो-चार होना पड़ता है। इसका असर मवेशियों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर और दतिया के साथ-साथ शिवपुरी, विदिशा और रायसेन जिलों को भी लाभ मिलेगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना के पूरा हो जाने से जहां 8 लाख 11 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा पहुंचाई जा सकेगी, वहीं 41 लाख लोगों को सहज तौर पर पीने का पानी मिल पाएगा।

प्रमोद भार्गव
(वरिष्ठ पत्रकार)